आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 05.11.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज तीसरे दिन भी जारी रहेगा। कार्य मंत्रणा समिति ने सत्र की अवधि एक दिन बढ़ाने का निर्णय लिया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। कहा– "विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड" के संकल्प के साथ प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- एम०डी०डी०ए की आढ़त बाजार से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रभावित परिसंपत्तियों के प्रतिकर वितरण और भूखंड आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
- कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 11 जोन और 36 सेक्टरों में विभाजित किया गया।

मुख्यमंत्री विधानसभा वि□ाश सत्र संबोधन

उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज तीसरे दिन भी जारी रहेगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित इस विशेष सत्र की अवधि कल एक दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड रजत जयंती के अवसर पर कल शाम देहरादून में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड "विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड" के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "2047 तक विकसित राष्ट्र" के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योगजना को वृहद रूप प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की आय वृद्धि दर में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है और राज्य की 'चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर' राष्ट्रीय औसत से चार गुना अधिक रही है।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया के तहत उत्तराखंड को 'लीडर' श्रेणी और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में 'टॉप अचीवर' श्रेणी का सम्मान मिला है। राज्य जीईपी इंडेक्स तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है और बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आई है। वित्तीय प्रबंधन में भी उत्तराखंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तथा हिमालयी राज्यों में विकास की दृष्टि से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना और प्रति व्यक्ति आय 18 गुना बढ़ी है।

मुख्यमंत्री विधानसभा वि�शेश सत्र संबोधन– 2

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण और कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है तथा नारी सशक्तिकरण, महालक्ष्मी, सशक्त बहना उत्सव और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

चिकित्सा सुविधाओं पर बोलते हुए श्री धामी ने कहा कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम हो रहा है और हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण प्रगति पर है। युवाओं के सम्मान और अवसरों की रक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए पहली बार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है तथा पिछले चार वर्षों में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति से प्रदेश की जनसांख्यिकी पर असर पड़ा, जिसे रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर सख्त कार्रवाई की गई है। अब तक नौ हजार एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है।

श्री धामी ने जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग करने का निर्णय लिया है और 1 जुलाई 2026 के बाद बिना मान्यता वाले मदरसे बंद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर किसी भी मदरसे की आड़ में राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चलाई जाएंगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बहस

विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने राज्य की स्थापना से अब तक के विकास पर अपने विचार रखे। भाजपा विधायकों ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया, जबकि विपक्ष ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार की आलोचना की।

भोजनावकाश के बाद दोबारा शुरू हुई कार्यवाही के दौरान राजपुर विधायक खजान दास, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी बात रखी। बनभुलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर भी सदन में जमकर बहस हुई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सरकारी जमीनों पर बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया, जबकि हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और अन्य कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध किया। विधायक चौहान ने कहा कि बाहरी लोग लगातार उत्तराखंड की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के बावजूद विकास की रफ्तार धीमी है और जनता अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं, विधायक खजान दास ने देहरादून में एलिवेटेड रोड परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की।

लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहज़ाद ने हरिद्वार को स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के लोगों को भी पहाड़ी क्षेत्रों की तरह समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सड़क चौड़ीकरण

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की आढ़त बाजार से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना को गति मिल गई है। प्रभावित परिसंपत्तियों के प्रतिकर वितरण और भूखंड आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। रजिस्ट्री कार्य के निष्पादन के लिए मुख्य अभियंता एच.सी.एस. राणा और संयुक्त सचिव गौरव चटवाल को अधिकृत किया गया है, और प्रत्येक प्रभावित संपत्ति की रजिस्ट्री व प्रतिकर वितरण का कार्य एक साथ शुरू कर दिया गया है।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि यह परियोजना देहरादून के केंद्रीय क्षेत्र में यातायात सुगमता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रभावित संपत्ति स्वामियों को उचित प्रतिकर और वैकल्पिक भूखंड देने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है तथा नागरिकों के सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित परिसंपत्तियों की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग के पक्ष में शुरू हो चुकी है। सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक बायीं ओर की संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए मुख्य अभियंता राणा और दायीं ओर की संपत्तियों के लिए संयुक्त सचिव चटवाल को नामित किया गया है।

भेंट

अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे स्वयं चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। साथ ही उन्होंने तत्काल प्रभाव से अस्पताल के उन्नयन का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अस्पताल की क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 बेड कर दी गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आम जनता को त्वरित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एम्स ऋषिकेश में उत्तराखंडवासियों के लिए विशेष काउंटर स्थापित करने की दिशा में तत्काल कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। इसी उद्देश्य से चौखुटिया में उप जिला चिकित्सालय के निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल के विस्तार से चौखुटिया और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा तथा उपचार में होने वाली देरी को रोका जा सकेगा।

कार्तिक पूर्णिमा स्नान

कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। मेला क्षेत्र को 11 जोन और 36 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जहां सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष तैनाती की गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्नान पर्व के लिए नियुक्त पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता बरतते हुए ड्यूटी निभाने करने को कहा।

श्री डोभाल ने बताया कि यातायात पुलिस, जल पुलिस, बम निरोधक दस्ता और घोड़ा पुलिस की टीमें भी तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

निरीक्षण

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। यह कार्यक्रम पुलिस लाइन रेसकोर्स में आयोजित होने वाली पुलिस रैतिक परेड और 8 नवंबर को होने वाले आयोजन से संबंधित है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंच, बैठक व्यवस्था, साउंड सिस्टम, सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, पार्किंग और अतिथियों के स्वागत जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य स्थापना दिवस का आयोजन भव्य और सफल हो, इसके लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। साथ ही स्वच्छता, प्रकाश और शांति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल की ड्यूटी, परेड रिहर्सल और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आकर्षक परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य पुलिस की विभिन्न इकाइयों के जवान भाग लेंगे।